भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6085

(दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए)

मेरठ में सामुदायिक रेडियो का संचालन

6085. श्री अरुण गोविलः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मेरठ जिले में कई विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान सामुदायिक रेडियो का संचालन कर रहे हैं और क्या ये रेडियो विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी योजनाओं के संबंध में ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं;

(ख) देश में संचालित सामुदायिक रेडियो को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में कार्य कर रहे सामुदायिक रेडियो की संख्या कितनी है;

(घ) जनता को शिक्षित करने में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार की सामुदायिक रेडियो को विज्ञापन या बजटीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो मेरठ लोक सभा क्षेत्र में नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): देश में 563 सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) प्रचालनरत हैं, जिनमें से पाँच (05) मेरठ में प्रचालनरत हैं।

सामुदायिक रेडियो को "भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता" नामक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य नए तथा मौजूदा

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) को संसाधनों, क्षमता तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुदृढ़ करना है। विशेष रूप से दूर-दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो के विकास को बढ़ावा देने हेतु इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। यह समुदायों को स्थानीय आवाजों तथा विकास प्रक्रियाओं में भागीदारी हेतु एक मंच प्रदान कर सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करता है।

स्कीम के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

- नए तथा मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) को उपकरणों की खरीद अथवा प्रतिस्थापन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना;
- सामुदायिक रेडियो संचालकों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण;
- फीडबैक प्राप्त करने, जागरूकता उत्पन्न करने तथा ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाओं, सेमिनारों तथा क्षेत्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन।

सरकार ने सामुदायिक रेडियो की सामग्री के अभिलेखीकरण तथा साझाकरण के लिए नेविगेट भारत पोर्टल पर एक सामग्री साझा करने का मंच भी विकसित किया है। यह स्टेशनों को गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम अपलोड करने तथा पुनः उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जिससे विकासात्मक तथा सांस्कृतिक सामग्री का एक केंद्रीकृत भंडार तैयार होता है। सीआरएस पर नीतिगत दिशानिर्देश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://mib.gov.in पर उपलब्ध हैं।

सरकार केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के माध्यम से सूचीबद्ध सीआरएस को सरकारी सूचनाओं के प्रसार हेतु सशुल्क विज्ञापन प्रदान कर उनको सहायता प्रदान करती है।

****